39. आयोग एवं अधिनियम

❐ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई-
[राजस्थान पु. कॉन्स्टेबल-15.7.2018 (I)][Asst. Jailer-15.3.2016]
(1) अनुच्छेद 243 Z (2) अनुच्छेद 243 K
(3) अनुच्छेद 243 A (4) अनुच्छेद 243 C
Ans. (2)

व्याख्या – *पंचायती राज संस्थाओं (अनुच्छेद 243 K) एवं शहरी निकायों (अनुच्छेद 243 ZA) में चुनाव कराने हेतु राजस्थान में राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग (एक सदस्यीय) का गठन किया गया है। 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित संविधान का अनुच्छेद 243ट (243K) यह व्यवस्था करता है कि-पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन अयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसका एक सचिव होगा जो राज्य का राज्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। अनुच्छेद 243यक (243ZA)-नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, अनुच्छेद 243ट (243 K) में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।*

❐ राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथनों पर विचार कर उत्तर दीजिए-
[RAS Pre Exam-19.11.2013]
(A) इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K के अन्तर्गत जुलाई 1994 में किया गया।
(B) यह एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है।
(C) इसका एक सचिव होता है जो राज्य का राज्य निर्वाचक अधिकारी भी होता है।
(D) यह पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है एवं चुनाव करवाता है।
(1) (A) एवं (D) (2) (B) एवं (D)
(3) (A), (C) एवं (D)
(4) (A), (B), (C) एवं (D)
Ans. (3) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❐ राज्य निर्वाचन आयोग है- [Asst. Jailer -15.03.2016]
(1) एक सदस्यीय (2) त्रिसदस्यीय
(3) द्वि सदस्यीय (4) बहु सदस्यीय
Ans. (1) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❐ राज्य का निर्वाचन आयोग है-[जेल प्रहरी 27-10-2018]
(1) एक वैधानिक संस्था (2) एक संवैधानिक संस्था
(3) एक कार्यपालिका संस्था
(4) भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई
Ans. (2) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❐ राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन-सा /से कथन सही है/हैं-[Assistant Professor-22.9.2021]
[R.A.S.- 27.10.2021]
1. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अधीन अप्रैल, 1994 में हुआ।
2. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है।
3. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है, जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है।
(1) केवल 1 (2) 1 एवं 2
(3) 2 और 3 (4) 1, 2 और 3
Ans. (3) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❐ राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही निर्णय का चुनाव कीजिए-
[पटवार-24.10.2021 (Shift - II)]
1. राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना।
2. पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए चुनाव सम्पन्न कराना।
3. भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची चयन और तैयार करने का कार्य।
(1) 2, 3 (2) 1, 2, 3
(3) 1, 2 (4) कोई नहीं
Ans. (3) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

Scanned with OKEN Scanner

❑ राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ-
[कॉलेज व्याख्याता (सारंगी) 30.5.2019][उद्योग निरीक्षक-24.6.2018]
[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-14.07.2018 (II), 08.11.2020 (II)]
[EO & RO : 14.5.2023 (S-II)][जेल प्रहरी 28-10-2018, S-II
[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-16.05.2022 (II)]
(1) जून, 1993 को (2) जुलाई, 1994 को
(3) अगस्त, 1995 को (4) सितम्बर, 1996 को
Ans. (2)

व्याख्या - राजस्थान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष -
- *प्रथम - अमर सिंह राठौड़ (1 जुलाई, 1994 से 1 जुलाई, 2000)*
- *द्वितीय - एन. आर. भसीन (2 जुलाई, 2000 से 2 जुलाई, 2002)*
- *तृतीय- इन्द्रजीत खन्ना (26 दिसम्बर, 2002 से 26 दिसम्बर, 2007)*
- *चतुर्थ - अशोक कुमार पाण्डे (1 अक्टूबर, 2008 से 30 सितम्बर, 2013)*
- *पंचम - राम लुभाया (1 अक्टूबर, 2013 से 31 मार्च, 2017)*
- *षष्ठ - प्रेम सिंह मेहरा (3 जुलाई, 2017 से 3 जुलाई, 2022)*
- *सप्तम- मधुकर गुप्ता (14 अगस्त, 2022 से ..)*

❑ माह अगस्त, 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया?
[III Grade (Math-Science) -25.2.2023]
[II Grade GK - 21.12.2022]
(1) श्री बी.एल. आर्य (2) श्री डी.बी. गुप्ता
(3) श्री मधुकर गुप्ता (4) श्रीमती ऊषा शर्मा
Ans. (3) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ राजस्थान का कौनसा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है?
[RAS Pre Exam-19.11.2013]
(1) अजमेर (2) मनोहरथाना (3) सादुलशहर (4) बानसूर
Ans. (3)

व्याख्या- भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा क्षेत्र के स्थान आवंटनों में गंगानगर के सादुलशहर को क्रमांक 1 पर रखा गया है जबकि झालावाड़ जिले का मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र को क्रमांक 200 पर रखा गया है। संसदीय क्षेत्र के स्थान आवंटनों में श्रीगंगानगर को क्रमांक 1 पर रखा गया है जबकि झालावाड़-बारां संसदीय क्षेत्र को क्रमांक 25 पर रखा गया है।

सादुलशहर मनोहरथाना
V. 1 200
संसदीय 1 25
क्षेत्र

❑ राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए:
[RAS-26.10.2013]
(A) राज्य के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है।
(B) राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है।
(C) राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है।
(D) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गये मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है।
कूट: (1) (A) और (B) (2) (C) और (D)
(3) (A), (B) और (D) (4) केवल (D)
Ans. (1)

व्याख्या- पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

❑ ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौनसे विधानसभा चुनाव में किया गया था?
[उद्योग निरीक्षक परीक्षा-24.06.2018]
(1) ग्याहरवाँ विधानसभा चुनाव 1998
(2) बारहवाँ विधानसभा चुनाव 2003
(3) तेरहवाँ विधानसभा चुनाव 2008
(4) चौदहवाँ विधानसभा चुनाव 2013
Ans. (4)

व्याख्या - चुनाव आयोग ने पहली बार वोटरों को 14वीं विधानसभा चुनाव में नोटा का विकल्प दिया, जिसमें राजस्थान में 1.9% मतदाताओं ने 'इनमें से कोई नहीं/नोटा' (None of the above – NOTA) के विकल्प को चुना। इलैक्ट्रॉनिक वॉटिंग मशीन (EVM) में नोटा अंतिम बटन (गुलाबी रंग) होता है।

Scanned with OKEN Scanner

❐ राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? [ANM-03.02.2024] [CET : 07.01.2023 (S-I)] [CET : 05.02.2023 (S-I)]

(1) ज्योति किरण (2) माणिक चंद सुराणा
(3) हीरालाल देवपुरा (4) कृष्ण कुमार गोयल

Ans. (4)

व्याख्या - राजस्थान वित्त आयोग अध्यक्ष-
- *प्रथम : गठन-24 अप्रैल, 1994, अध्यक्ष-कृष्ण कुमार गोयल, कार्यकाल-1अप्रैल, 1995 से 31मार्च, 2000*
- *द्वितीय : गठन - 7 मई, 1999, अध्यक्ष-हीरालाल देवपुरा, कार्यकाल - 1 अप्रैल, 2000 - 31 मार्च, 2005*
- *तृतीय : गठन - मई, 2004, अध्यक्ष- माणिक चन्द सुराणा, कार्यकाल -1 अप्रैल, 2005 - 31 मार्च, 2010*
- *चतुर्थ : गठन-13 अप्रैल, 2011, अध्यक्ष- डॉ. बी. डी. कल्ला, कार्यकाल-1 अप्रैल, 2010 - 31 मार्च, 2015*
- *पंचम : गठन -जुलाई, 2014, अध्यक्ष- डॉ. ज्योति किरण, कार्यकाल -1 अप्रैल, 2015 - 31 मार्च, 2020*
- *छठा : गठन-12 अप्रैल, 2021, अध्यक्ष- प्रद्युम्न सिंह, कार्यकाल -1 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2025*

❐ राजस्थान के पाँचवें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कौनसा है- [राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-08.11.2020 (II)]

(1) 2016-21 (2) 2017-22
(3) 2015-20 (4) 2014-19

Ans. (3) *व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❐ आजकल राजस्थान में कौनसा 'राज्य वित्त आयोग' कार्य कर रहा है? [कनिष्ठ लेखाकार -11.02.2024]

(1) छठा (2) पाँचवाँ (3) सातवाँ (4) चौथा

Ans. (1) *व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❐ निम्न में से किसको राजस्थान में 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है- [संगणक-03.03.2024][संगणक परीक्षा -19.12.2021] [CET -11.2.2023 (S-II)] [CET : 07.01.2023 (S-II)]

(1) मोहन कृष्ण बोहरा (2) हेम सिंह शेखावत
(3) भँवर लाल शर्मा (4) प्रद्युमन सिंह

Ans. (4) *व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❐ राज्य वित्त आयोग, राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नांकित में से कौनसा सुमेलित नहीं है-[Asst. Professor- 7.1.2024]

(1) प्रद्युम्न सिंह 2020-2021 से 2024-2025
(2) ज्योति किरण 2010-2011 से 2014-2015
(3) माणिक चंद सुराणा 2005-2006 से 2009-2010
(4) हीरालाल देवपुरा 2000-2001 से 2004-2005

Ans. (2) *व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❐ राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में कौनसा कथन सही नहीं है- [Asst. Professor- 7.1.2024]

(1) आयोग का गठन दिसम्बर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था।
(2) अशोक लाहोटी आयोग के सदस्य थे।
(3) आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह थे।
(4) अंतिम रिपोर्ट सितम्बर, 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई।

Ans. (1) *व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❐ पंचायतों के लिये गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत उल्लिखित है? [द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा-26.04.2017]

(1) अनुच्छेद-243. झ (2) अनुच्छेद - 243 ड
(3) अनुच्छेद - 243 ख (4) अनुच्छेद - 243 ज

Ans. (1)

व्याख्या- पंचायती राज संस्थाओं (अनुच्छेद 243 I/झ) एवं शहरी निकायों (अनुच्छेद 243 Y/म) की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने हेतु राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कार्यग्रहण की तिथि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होता है।

❐ राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है-

(1) राज्यपाल को (2) राज्य के वित्त मंत्री को
(3) मुख्यमंत्री को (4) राज्य के वित्त सचिव को

Ans. (1) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❐ राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? [प्रवक्ता (तकनीकी शिक्षा विभाग) -12.03.2021] [पटवार-23.10.2021 (S-I)][JEN (Electric) Degree - 18.5.2022] [RAS-28.08.2016][राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-15.05.2022 (II)]

(1) 18 अप्रैल, 2005 (2) 18 अप्रैल, 2007
(3) 18 अप्रैल, 2006 (4) 18 अप्रैल, 2008

Ans. (3)

Scanned with OKEN Scanner

व्याख्या – राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल, 2006 को किया गया है। राज्य सूचना आयोग केन्द्रीय सूचना आयोग की तरह एक सांविधिक एवं स्वायत्तशासी निकाय है।

☐ निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? [उद्योग निरीक्षक-24.06.2018]
(1) यह एक सांविधिक निकाय है।
(2) यह स्वायतशासी निकाय है।
(3) इसका गठन 18 अप्रैल, 2005 को हुआ था।
(1) सिर्फ 1 (2) सिर्फ 1 व 2 (3) 1, 2, व 5 (4) सिर्फ 3
Ans. (2) *व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

☐ राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे- [पटवार-24.10.2021 (Shift -I)]
(1) श्री एन. के. जैन (2) श्री अमरजीत सिंह
(3) श्री एम.डी. कौरानी (4) श्री इन्द्रजीत खन्ना
Ans. (3)

व्याख्या - राजस्थान सूचना आयोग अध्यक्ष-
- *प्रथम : एम.डी. कोरानी -18 अप्रैल, 2006*
- *द्वितीय : टी. श्रीनिवासन - 05 सितम्बर, 2011*
- *तृतीय : सुरेश कुमार चौधरी- 06 नवम्बर, 2015*
- *चतुर्थ : देवेन्द्र भूषण गुप्ता-11 दिसम्बर 2020*
- *पंचम : मोहन लाल लाठर-09 जुलाई 2024 से निरन्तर*

☐ कौन-सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता हैं? [RAS-19.11.2013] [JEN (Civil) Degree - 18.05.2022]
(1) राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है।
(2) राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश
(3) राज्य विधान सभा में विरोधीदल का नेता
(4) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित एक मंत्रिमण्डलीय मंत्री
Ans. (2)

व्याख्या- राज्य सूचना आयोग (अधिनियम की धारा 15) गठन- राज्य सूचना आयोग, केन्द्रीय सूचना आयोग की तरह एक सांविधिक एवं स्वायत्तशासी निकाय है। राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं आवश्यकतानुसार (अधिकतम 10) सूचना आयुक्त होंगे, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित समिति की सिफारिश पर की जाएगी-
(I) मुख्यमंत्री- समिति के अध्यक्ष।
(II) विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता।
(III) मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री।
इनकी योग्यताएँ एवं अयोग्यताएँ वही हैं जो केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त य अन्य सूचना आयुक्तों के लिए निर्धारित हैं।

☐ राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है- [पटवार-24.10.2021 (S-II)] [PSI - 14.09.2021]
(1) मुख्य सचिव (2) मुख्यमंत्री (3) राष्ट्रपति (4) राज्यपाल
Ans. (4) *व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

☐ राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका सदस्य नहीं होता है-[उद्योग निरीक्षक परीक्षा-24.06.2018]
(1) मुख्यमंत्री (2) विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता
(3) मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री
(4) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
Ans. (4) *व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

☐ राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है? [जेल प्रहरी परीक्षा - 2017]
(1) 6 वर्ष (आयु की कोई सीमा नहीं)
(2) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
(3) 5 वर्ष (आयु की कोई सीमा नहीं)
(4) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
Ans. (2)

व्याख्या -राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि : सभी के लिए पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो। केन्द्र सरकार ने सूचना का अधिकार (संशोधन) कानून 2019 द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल को घटकार 3 वर्ष या 65 वर्ष तक कर दिया है।

☐ मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों को राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है- [राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-13.06.2024 (I)]
(1) स्वयं राज्यपाल द्वारा (2) मुख्यमंत्री द्वारा
(3) मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर
(4) राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर
Ans. (1)

Scanned with OKEN Scanner

❐ निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें-

1. राजस्थान सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था।

2. राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है।

[Protection Officer -28.01.2023]

(1) कथन 1 सत्य है। (2) कथन 2 सत्य है।
(3) कथन 1 और 2 सत्य है। (4) दोनों कथन असत्य है।

Ans. (1)

व्याख्या *- सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर शिकायत या अपील पर निर्णय देते समय आयोग देरी से सूचना देने, सूचना को खुर्द-बुर्द करने, रुकावट डालने आदि के आरोपों के दोषी लोक सूचना अधिकारी पर 250/- रुपये प्रतिदिन की दर से दण्डारोपण कर सकता है जो राशि अधिकतम 25000/- तक हो सकती है।*

❐ राजस्थान सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? [CET : 07.01.2023 (S-1), 08.01.2023 (S-II)]

(1) 30000 (2) 20000
(3) 15000 (4) 25000

Ans. (4) ***व्याख्या*** *- उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❐ निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है?

[Protection Officer -28.01.2023]

(1) अपने संगठन की विशिष्टयाँ, कृत्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना।
(2) प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना।
(3) सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पवित्र करना जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने।
(4) सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कम्प्यूटरीकरण।

Ans. (2)

व्याख्या *-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक सूचना प्राधिकारी ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।*

❐ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी है? [जेल प्रहरी परीक्षा - 2017]

(1) लोक सूचना आयुक्त (2) लोक सूचना सचिव
(3) लोक सूचना अधिकारी (4) लोक सूचना प्रशासक

Ans. (3)

व्याख्या *- लोक सूचना अधिकारी : सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के तहत लोक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्रशासनिक इकाईयों/कार्यालयों में नियुक्त वे अधिकारी 'लोक सूचना अधिकारी' कहे जाते है, जिन्हें आवेदकों को आवेदित सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। विभागाध्यक्षों के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।*

❐ निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही कूट चुनिए-

(i) सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है।

(ii) अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया।

[CET : 08.01.2023 (S-II)]

(1) केवल (i) सही है
(2) केवल (ii) सही है
(3) न तो (i) ना ही (ii) सही है
(4) दोनों कथन सही हैं

Ans. (4)

व्याख्या *- आमजन की सभी उपयोगी सूचनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने तथा उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 15 जून, 2005 से राजस्थान सहित सम्पूर्ण देश में प्रभावी हो गया। इसके कुछ प्रावधान तुरन्त तथा अधिकांश 12 अक्टूबर, 2005 से लागू किये गये।*

❐ 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' की किस धारा के अन्तर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा-

[Assistant Professor-22.9.2021]

(1) 19(4) (2) 19(5) (3) 19(6) (4) 19(7)

Ans. (4)

Scanned with OKEN Scanner

❐ 'राजस्थान सम्पर्क' पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है- [प्रवक्ता (तकनीकी शिक्षा विभाग) -12.03.2021]
(1) आर.टी.आई. के तहत सूचना एकत्र करने के लिए।
(2) शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में।
(3) लोकसेवाओं के प्रदान की गारन्टी के लिए
(4) सामाजिक अंकेक्षण मंच के रूप में
Ans. (2)

व्याख्या – राजस्थान सम्पर्क जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण हेतु 2014 में शुरू किया गया। इसमें बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा है।

❐ राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया- [प्रवक्ता (तकनीकी) -12.03.2021]
[II Grade (SST) - 21.12.2022]
(1) अप्रैल, 2019 में (2) अगस्त, 2019 में
(3) जनवरी, 2020 में (4) अक्टूबर, 2020 में
Ans. (2)*

व्याख्या – **जन सूचना पोर्टल** – जन सूचना पोर्टल का उद्घाटन 20 अगस्त, 2019 को ITD समारोह में किया गया। सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा जनसूचना पोर्टल विकसित किया गया है।

❐ जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए- [Asst. Professor- 7.1.2024]
(1) यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है।
(2) ई-मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है।
(3) इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आई डी आवश्यक है।
(4) यह ITI अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अन्तर्गत माँगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है।
Ans. (3)

❐ सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसम्बर, 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में की गई- [प्रवक्ता (तकनीकी शिक्षा विभाग) -12.03.2021]
(1) पब्लिक वेलफेयर पोर्टल (2) राजस्थान वेलफेयर पोर्टल
(3) योजना वेलफेयर पोर्टल (4) इनमें से कोई नहीं
Ans. (1)

व्याख्या – सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु 18 दिसम्बर, 2020 को जनकल्याण पोर्टल (Public Welfare Portal) का शुभारम्भ किया गया।

❐ राजस्थान राज्य महिला आयोग है- [उद्योग प्रसार अधिकारी-22.08.2018]
(1) संवैधानिक निकाय (2) नियामकीय निकाय
(3) अध्यादेश द्वारा बनाया गया है (4) सांविधिक निकाय
Ans. (4)

व्याख्या – राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल, 1999 को एक विधेयक राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित हो जाने पर 15 मई, 1999 को राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके सांविधिक निकाय राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन (एक अध्यक्ष एवं तीन सदस्य) कर दिया गया।

❐ किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई- [VDO-28.12.2021 (S-I)]
(1) 1996 (2) 1997 (3) 1998 (4) 1999
Ans. (4) **व्याख्या** - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

❐ राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौनसा/कौनसे कथन सत्य है/हैं- [VDO-27.12.2021 (S-I)]
1. आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 2. आयोग का गठन 15 मई, 1999 को हुआ। 3. यह गैर-संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। 4. इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जाँच करना है।
(1) 1, 2, 3 (2) 2, 3, 4 (3) 1, 2 (4) 1, 2, 3, 4
Ans. (2) नियुक्ति : राज्य सरकार द्वारा मनोनीत

❐ फरवरी, 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? [वनपाल-6.11.2022(I)]
(1) सुमन शर्मा (2) अन्जना मेघवाल
(3) सुमित्रा जैन (4) रेहाना रियाज चिश्ती
Ans. (4)

व्याख्या – राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष –
1. कांता कथुरिया : 1999 से 2002
2. पवन सुराणा : 2003 से 2006
3. तारा भण्डारी : 2006 से 2009
4. लाड कुमारी जैन : 2011 से 2014
5. सुमन शर्मा : 2015 से 2018
6. रेहाना रियाज चिश्ती : 11.02.2022 से 10.02.2025

Scanned with OKEN Scanner

❑ निम्नांकित में से कौन राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं- [Asst. Professor- 7.1.2024]
(1) लाड कुमारी जैन (2) सुमन शर्मा
(3) नगेन्द्र बाला (4) पवन सुराणा
Ans. (3) *व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है- [कॉलेज व्याख्याता परीक्षा-2016]
(1) महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना।
(2) महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना।
(3) महिला सशक्तीकरण हेतु प्रयास।
(4) महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना।
Ans. (4)

व्याख्या - *राजस्थान राज्य महिला आयोग के मुख्य कार्य (धारा 11) - (1) महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जाँच कर, विनिश्चय करके उस मामले में सरकार को सिफारिश करना। (2) प्रवृत्त विधियों व उनके प्रवर्तक को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना। (3) राज्य लोकसेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना। (4) महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना। (5) आयोग की दृष्टि में यदि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सरकार से सिफारिश करना। (6) महिलाओं से सम्बन्धित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना तथा महिलाओं को समुचित न्याय मिले इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करना।*

❑ राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 की कौनसी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है- [Asst. Professor- 7.1.2024]
(1) धारा 13 (2) धारा 12 (3) धारा 11 (4) धारा 10
Ans. (3) *व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ जनसमस्याओं के निराकरण के लिए निम्नांकित में किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? [राज.पुलिस कॉन्स्टेबल-14.06.2024 (II)] [RAS-28.8.2016]
(1) सुनवाई का अधिकार अधिनियम
(2) सुशासन अधिनियम
(3) लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम
(4) लोक प्रापण में में पारदर्शिता अधिनियम
Ans. (1)

व्याख्या - *आम आदमी की समस्याओं तथा अभाव अभियोगों पर उनके अपने क्षेत्र में ही एक निश्चित समय सीमा में सुनवाई का अधिकार (Right to Hearing Act - 2012) 1 अगस्त 2012 से राज्य में लागू किया गया है।*

❑ राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? [VDO Mains -09.07.2022]
(1) 2010 (2) 2014 (3) 2012 (4) 2018
Ans. (3) *व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ- [EO & RO : 14.05.2023 (S-I)] [महिला पर्यवेक्षक-06.01.2019] [प्रवक्ता (तकनीकी शिक्षा विभाग) -12.03.2021] [JEN (Mechanical) Diploma- 20.05.2022] [JEN (Civil) Degree - 18.05.2022]
(1) 14 नवम्बर, 2011 (2) 31 अक्टूबर, 2011
(3) 21 मई, 2011 (4) 2 अक्टूबर, 2011
Ans. (1)

व्याख्या : राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम, 2011 - 14 नवम्बर, 2011 से आरम्भ एक ऐसा अधिनियम जो जनता से जुड़े 15 विभागों के 53 विषयों की 108 (अब 27 विभाग 287 सेवाएँ) सेवाओं को समयबद्ध व पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। मध्यप्रदेश (सर्वप्रथम), बिहार में यह कानून लागू है। लेकिन, इतने विभाग व काम शामिल करने वाला राजस्थान पहला राज्य है।

❑ राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 का उद्देश्य है- [JEN (Electric) Degree - 18.05.2022]
(1) पारदर्शिता लाना
(2) शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना
(3) सेवा प्राप्ति का अधिकार देना
(4) उपर्युक्त सभी
Ans. (4) *व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ राजस्थान लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? [CET : 07.01.2023 (S-I)]
(1) 60 दिन (2) 45 दिन (3) 30 दिन (4) 15 दिन
Ans. (1)

Scanned with OKEN Scanner

व्याख्या–यदि किसी व्यक्ति का आवेदन नामंजूर हो जाये या निर्धारित समय-सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है तो 30 दिन के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील की जा सकती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिन के अन्दर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को दूसरी अपील की जा सकती है। द्वितीय अपीलीय अधिकारी सेवा प्रदान करने का आदेश प्रदान करने के लिए साथ नामित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी पर दण्ड अधिरोपित कर सकता है। किसी विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी उसकी परिधि में घोषित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में प्रदान नहीं करता है तो, कम से कम 500 रु. से लेकर अधिकतम 5000 रु. तक के आर्थिक दंड का प्रावधान। यदि वह सेवा प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब करता है तो प्रतिदिन 250 रुपये (अधिकतम 5000 रुपये) का आर्थिक दण्ड।

❐ निम्नांकित वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें- [Asst. Professor- 7.1.2024]

1. राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारण्टी अधि-नियम, 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध, निर्णय के तीस दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है।
2. राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारण्टी अधि-नियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी तीस दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने के पर्याप्त कारण है।

(1) 1 सही नहीं हैं, किन्तु 2 सही है।
(2) 1 सही है, किन्तु 2 सही नहीं है।
(3) 1 व 2 दोनों सही नहीं है।(4) 1 व 2 दोनों सही हैं।

Ans. (3)

❐ राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ- [CET : 07.01.2023 (S-II)] [R.A.S.- 27.10.2021]

(1) 11 जनवरी, 2021 को(2) 18 दिसम्बर, 2019 को
(3) 11 जनवरी, 2020 को(4) 18 दिसम्बर, 2020 को

Ans. (2)

व्याख्या–राजस्थान सरकार 18 दिसम्बर, 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकार अध्यादेश 2019 लागू किया तथा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 28 फरवरी, 2020 को पारित किया गया।

❐ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? [JEN (Civil) Diploma - 18.05.2022]

(1) 1950 (2) 1952 (3) 1955 (4) 1956

Ans. (4)

व्याख्या – राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, 1 जुलाई 1956 से लागू किया गया। इस अधिनियम का विस्तार आबू, अजमेर और सुनैल क्षेत्र में भी हुआ, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 37) की धारा 10 के तहत राजस्थान राज्य में मिला दिये गये किन्तु इस अधिनियम का आबू, अजमेर और सुनैल क्षेत्रों में दिनांक 15.6.1958 से अधिसूचना क्रमांक एफ (281) राजस्व-II/56 दिनांक 23.3.1958 द्वारा विस्तार हुआ। यह अधिनियम सभी श्रेणियों के राजस्व न्यायालयों और कार्यालयों की स्थापना, उनकी शक्तियों और प्रक्रियाओं, भूमि और उसके उपयोग, सर्वेक्षण, रिकॉर्ड नियंत्रण तथा भू-प्रबन्धन कार्य, सम्पदाओं का बंटवारा, राजस्व का संग्रहण और अन्य विविध मामलों जैसे लागत की वसूली आदि से संबंधित है।

❐ राजस्थान में राजस्व मण्डल की स्थापना कब हुई? [JEN (Mechanical) Diploma- 20.05.2022] [CET : 08.01.2023 (S-I)] [वनरक्षक-11.12.2022(S-II)]

(1) 1949 (2) 1959 (3) 1969 (4) 1979

Ans. (1)

व्याख्या–राजस्व मण्डल का मुख्यालय, अजमेर में है। राजस्व मण्डल का प्रथम अध्यक्ष बृजचन्द शर्मा थे। राज्य में भू-अभिलेखों, भू-राजस्व एवं भू-प्रबंध की व्यवस्था हेतु 1 नवम्बर, 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना की गई। यह एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-judicial) है। वर्तमान में राजस्व मंडल अपने मूल कार्यों के अलावा कृषि संबंधी आँकड़े, पशुगणना एवं सिंचाई संबधी आँकड़े भी एकत्रित करता है।

❐ राजस्थान में प्रथम 'राजस्व दिवस' का आयोजन कब हुआ- [प्रवक्ता (तकनीकी शिक्षा विभाग) -12.03.2021]

(1) 15 सितम्बर, 2019 (2) 15 अक्टूबर, 2019
(3) 15 सितम्बर, 2020 (4) 15 अक्टूबर, 2020

Ans. (4)

व्याख्या–15 अक्टूबर, 1955 को राजस्थान काश्तकारी कानून प्रदेश में लागू हुआ था और खेत जोतने वाले काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिले थे, इसलिए 15 अक्टूबर, 2020 को राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस मनाया गया।

Scanned with OKEN Scanner

❐ राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है?
[III Grade Teacher-2006][VDO-27.12.2021 (S-I)]
(1) जयपुर (2) अजमेर (3) कोटा (4) जोधपुर
Ans. (1)

व्याख्या - राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (Rajasthan Civil Services Appellete Tribunal) : इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान है। राज्य कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों तथा आनुषंगिक विवादों के निपटारे के लिए राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 के तहत 1 जुलाई, 1976 को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का गठन किया गया था। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जयपुर स्थाई पीठ के क्षेत्राधिकार में जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा के जिलों को तथा जोधपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों को शामिल किया गया।

❐ राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए- [II Grade (GK) 29.1.2023]
(1) अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर
(2) उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा
(3) जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा
(4) भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर
Ans. (3) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❐ जयपुर, उदयपुर और जोधपुर की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की जानकारी साझा करने हेतु राजस्थान ने जून, 2016 में....मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारम्भ किया- [Assistant Archivist-03.08.2024]
[Asst. Town Planner- 16.06.2023]
[ARO-28.8.2022] [पशुधन सहायक 04.5.2022]
(1) राजवायु (2) वायुराज (3) राजहवा (4) हवाराज
Ans. (1)

व्याख्या - मोबाइल ऐप 'राज वायु' : राज्य मण्डल द्वारा 'राज वायु' नामक वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी हेतु मोबाइल ऐप 5 जून, 2016 को लॉन्च किया गया। यह मोबाइल 'ऐप' यूनिसेफ, राजस्थान सरकार, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान एवं भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है।

❐ राज्य मंत्रिमण्डल ने एक प्राधिकरण (अथॉरिटी) गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो राजस्थान राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जनसंतुष्टि एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस प्राधि-करण का नाम है-[स्कूल व्याख्याता(सं. वि.)- 15.11.2022]
(1) राज. जनकल्याणकारी योजना अंकेक्षण प्राधिकरण
(2) राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण
(3) राज. सामाजिक एवं निष्पादन जवाबदेही प्राधिकरण
(4) राजस्थान जनकल्याणकारी योजना जवाबदेही प्राधिकरण
Ans. (2)

व्याख्या- राजस्थान सरकार ने योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने वाले सरकारी विभाग, उपक्रमों और अन्य एजेंसियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी (1 सितम्बर, 2022) दी है।

❐ राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई?
[CET : 07.01.2023 (S-1)]
(1) 1954 (2) 1955 (3) 1956 (4) 1953
Ans. (4)

व्याख्या- जुलाई, 1953 में पहली बार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नियोजन विभाग की स्थापना की गई।

❐ हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है-
[प्रवक्ता (तकनीकी शिक्षा विभाग) -12.03.2021]
(1) बृज मोहन गर्ग (2) जगदीश प्रसाद
(3) हरि प्रसाद शर्मा (4) भगवाना राम विश्नोई
Ans. (3)

व्याख्या- कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष
- ☞ *रामखिलाड़ी मीणा (प्रथम अध्यक्ष) -10.10.2014 से 17.03.2017*
- ☞ *डॉ. नन्द सिंह नरूका (कार्यवाहक)- 17.03.2017 से 23.02.2018*
- ☞ *डॉ. बी.एल. जाटावत - 24.02.2018 से 16.01.2021*
- ☞ *हरि प्रसाद शर्मा - 30.01.2021 से 17.08.2023*
- ☞ *मेजर जनरल आलोक राज - 17.08.2023 से .....*

Scanned with OKEN Scanner